



# भारत का राजगान

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1993 (ज्येष्ठ 8, 1915)  
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1993 (JYAISTA 8, 1915)

इस भाग में भिन्न घृष्ण संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के बंकालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितरे नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ

515

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के बंकालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएँ

595

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएँ

3

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएँ

975

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम

\*

भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ

\*

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिन तथा रिपोर्ट

\*

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के बंकालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आवि भी शामिल हैं)

\*

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के बंकालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर), और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ

\*

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के बंकालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)

\*

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

\*

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महासेवा-परीक्षक, संघ सोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ

551

भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएँ और नोटिस

411

भाग III—खण्ड 3—मुद्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन संवय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ

\*

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएँ जिनमें सांविधिक नियायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं

12033

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस

67

भाग V—प्रधेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दस्ति वाला गन्पूरक

\*

## CONTENTS

PAGE	PAGE		
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.</b>	<b>515</b>	<b>PART II —SECTION 3—SUB SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)</b>	<b>*</b>
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .</b>	<b>595</b>	<b>PART II —SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence</b>	<b>*</b>
<b>PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence</b>	<b>3</b>	<b>PART III —SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India</b>	<b>551</b>
<b>PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence</b>	<b>975</b>	<b>PART III —SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs</b>	<b>411</b>
<b>PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations</b>	<b>*</b>	<b>PART III —SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners</b>	<b>*</b>
<b>PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations</b>	<b>*</b>	<b>PART III —SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies</b>	<b>12033</b>
<b>PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills</b>	<b>*</b>	<b>PART IV —Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies</b>	<b>67</b>
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b>	<b>*</b>	<b>PART V —Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi</b>	<b>*</b>
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b>	<b>*</b>		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 1993

शुद्धि पत्र

सं० 68-प्रेज/93—‘विशेषोल्लेख’ से संबंधित भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में शनिवार 28 जुलाई, 1990 को प्रकाशित इस सचिवालय की 26 जनवरी, 1990 की अधिसूचना सं० 54-प्रज/90 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्र० सं० 84. 13613007 लांस नायक जश ठाकर सिंह,  
9 पैरा कमांडो के स्थान पर

क्र० सं० 84. 13613007 लांस नायक जश ठाकर सिंह,  
9 पैरा कमांडो पढ़ें।

गिरीश प्रधान,  
निदेशक

शुद्धि पत्र

सं० 69-प्रेज/93—‘वीरचक’ पुरस्कार से संबंधित भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में शनिवार 27 अप्रैल, 1991 को प्रकाशित इस सचिवालय की 26 जनवरी, 1991 की अधिसूचना सं० 55-प्रेज/91 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम सं० 2. जहां भी 13613007 हवलदार जश ठाकर,  
पैराशूट रेजिमेंट (मरणोपरान्त) आए, के स्थान पर

क्रम सं० 2. 13613007 हवलदार जश ठाकर सिंह,  
पैराशूट रेजिमेंट (मरणोपरान्त) पढ़ें।

गिरीश प्रधान,  
निदेशक

## शुद्धि पत्र

सं० 70-प्रेज/93—“विशिष्ट सेवा मेडल” पुरस्कार से संबंधित भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में शनिवार 4 जुलाई, 1992 को प्रकाशित इस सचिवालय की 26 जनवरी 1992 की अधिसूचना सं० 96-प्रेज/92 में निम्नलिखित सं० संशोधन किया जाता है

क्रम सं० 94. जी/161718 सुपरिटेंडेंट इ० आर० प्रेड II, सतीश चन्द्र। के स्थान पर

क्रम सं० 94 जी/161718 सुपरिटेंडेंट बी० आर० प्रेड-II सतीश चन्द्र। पढ़ें

गिरीश प्रधान,  
निदेशक

(इलेक्ट्रानिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 मार्च 1993

## संकल्प

सं० आर ई/7.27/93—इस विभाग के दिनांक 30 जुलाई, 1990 के समसंख्यक संकल्प के सिलसिले में राष्ट्रपति जी ने स्वयंसेवी अभिकरण स्थायी समिति (स्कोवा) जिसे इलेक्ट्रानिकी विभाग सलाहकार मण्डल के रूप में भी जाना जाता है, का पुनर्गठन किया है, जो तत्काल प्रभावी होगा।

2. सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में, जनता की सृजनात्मक शक्तियों तथा विचारों का लाभ उठाने और सरकार के सभी कार्यों में स्वयंसेवी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के उद्देश्य से इस स्थायी समिति की जरूरत है, जैसा कि हाल ही में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत (डी ए आर पी जी) विभाग द्वारा बल दिया गया है।

इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि इलैक्ट्रानिक्स के लाभ साधारण जनता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचे, “स्कोवा” से यह अवैधता की जाती है कि वह जनता के साथ-साथ स्व-नियंत्रित संस्थानों की प्रभावी सहभागिता प्राप्त करने के लिए

सभी साधनों का उपयोग करे। 'स्कोवा' द्वारा ऐसे स्वयंसेवी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी संगठनों का निरंतर पता लगाया जाएगा जो इलेक्ट्रानिकी विभाग के कार्य के उन पहलुओं में शामिल हो सकते हैं, जिनमें एकता के साथ अधिक सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। ये पहलू इस प्रकार हो सकते हैं :— (i) अनुसंधान तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, (ii) इलेक्ट्रानिकी विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों तथा मिशनों के बीच धनराशि का आपस में आवंटन; (iii) विभिन्न परिषदों तथा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना इत्यादि

3. 'स्कोवा' निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कार्य करेगा :—

3.1 इलेक्ट्रानिकी विभाग को उन कार्यक्रमों, विशेष-कर अनुसंधान तथा विकास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जानकारी उपलब्ध कराना जो आस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं।

3.2 स्वयंसेवी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी संगठनों को इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीतियों तथा कार्य-क्रमों के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के एक मंडल के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाना और यहां तक कि विचारणीय नीतियों तथा कार्यक्रमों की सक्षमता तथा वांछनीयता के बारे में निर्णय लेने के लिए भी सक्षम बनाना।

3.3 इलेक्ट्रानिकी विभाग के कार्य में स्वयंसेवी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावी प्रतिभागिता के लिए भिन्न-भिन्न तंत्रों का निरंतर पता लगाना।

4. समिति का संशोधित गठन नीचे लिखे दिए गए अनुसंधानों का :—

1. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग अध्यक्ष

2. प्रबंधक ट्रस्टी उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वयंसेवी संगठन (वायस)

3. महाप्रबंधक (अभिनव आर डी) सदस्य कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (नाबाई)

4. अध्यक्ष राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सदस्य

5. अध्यक्ष	इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी संस्था (एसईसीटी) भीपाल	सदस्य
6. निदेशक	प्रायोगिक इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान केन्द्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	सदस्य
7. अध्यक्ष	सूचना विज्ञान अनुसंधान संस्थान	सदस्य
8. डॉ. परमेश्वर राव	सचिव भगवतुला चैरिटेनल ट्रस्ट, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
9. डॉ. सुत्रन सिन्हा	अध्यक्ष जन विज्ञान नेटवर्क	सदस्य
10. निदेशक	ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय मिशन, नरेन्द्रपुर, पश्चिमी बंगाल	सदस्य
11. श्री एम० आर० चक्रवर्ती	निदेशक इलेक्ट्रानिकी डिजिट तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी ई डी टी), इमफाल	सदस्य
12. श्री जोय मादिथ,	कार्यकारी निदेशक ग्राम विकास, उडिया	सदस्य
13. श्री प्रेम भाई	अध्यक्ष बनवासी सेवा आश्रम, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14. श्री संजय घोष	उर्मुल ट्रस्ट, राजस्थान	सदस्य
15. डॉ. विनय धर्माधिकारी	निदेशक, इलेक्ट्रानिकी विभाग	सदस्य-सचिव

5. "स्कोवा" की बैठकों में निम्नलिखित स्थायी आमंत्रिति होंगे :—

1. मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रमुख
2. नियन्त्रण तथा यंत्रीकरण प्रभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रमुख ।
3. दूरसंचार प्रभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रमुख
4. अनुसंधान तथा विकास समन्वय प्रभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रमुख
5. आर्थिक सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग
6. लघु उद्योग विकास आयुक्त (डी सी-एस एस आई) के कार्यालय के प्रतिनिधि
7. अध्यक्ष सदस्य सचिव को एक या अधिक ऐसे प्रतिनिधित्व व्यक्तियों को सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, जिनका योगदान इस मंच में अधिक उपयोगी होगा ।
8. इस "स्कोवा" के कार्यकलापों तथा बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को विभाग की सामान्य नीतियों के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।
9. बैठकों के लिए किया गया व्यय आमीण इलेक्ट्रानिकी बजट के अन्तर्गत मद्दत सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य ज्ञेयों, को प्रेषित किया जाए तथा इस संकल्प को समन्वय सूचना के लिए भारत के राजनव में प्रकाशित किया जाए ।

डा० प्रणव सेन,  
संयुक्त सचिव तथा आर्थिक सलाहकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 1993

आदेश

विषय :— तेल और प्राकृतिक गैस अयोग को कृष्णा गोदावरी बेसिन में के० जी०-ओ० एस० 90/1 ब्लाक के 4367 व० कि० मी० क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की मंजूरी ।

सं० : ओ-12012 / 31 / 92-ओ एन जी डी-4— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसके पश्चात आयोग कहा गया है) कृष्णा गोदावरी बेसिन में के० जी०-ओ० एस०-90/1 ब्लाक के 4367 व० क० मी० क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 1 अक्टूबर, 1992 (1-10-1992) से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण व्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केंसिंग हैड कन्डे-स्टेट पर 481/- स्पेशल प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी ।

- (घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैरिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा।
- (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।
- (च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ष किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—
- (1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8.00 रुपये
  - (2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40.00 रुपये
  - (3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200.00
  - (4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400.00 रुपये
  - (5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और तीसरे वर्ष के लिए 600.00 रुपये
- (छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।
- (ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण प्रिपोर्ट गुप्त रूप से लेगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।
- (झ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जिनना की आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।
- (ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) पर
- पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।
- (ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।
- (ठ) आयोग खुदाई / अन्वेषी आपरेशनों / सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथी-मीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंदालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- (इ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।
- (ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।
- (त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयारी की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
- भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।
- अनुसूची—"क"
- कृष्णा गोदावरी बेतिन ब्लाक के जी और एस 90/1 के लिए 4367 व० कि मी॰ क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांक
- | पाइंट | अक्षांतर                 | देशान्तर                 |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| ए     | $15^{\circ} 21' 00''$ एन | $80^{\circ} 40' 25''$ ई. |
| बी    | $15^{\circ} 21' 00''$ एल | $80^{\circ} 34' 10''$ ई  |
| सी    | $15^{\circ} 50' 54''$ एन | $80^{\circ} 31' 31''$ ई  |
| डी    | $14^{\circ} 58' 15''$ एन | $80^{\circ} 03' 46''$ ई  |
| ई     | $14^{\circ} 58' 90''$ एन | $80^{\circ} 40' 25''$ ई  |

अनुसूची-ब

अशोधित तेल, केरिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण  
के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

## क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

## (क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

## (ख) केरिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु- मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

## (ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त धन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए धन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये धन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त धन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्वारा मैं श्री..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ  
के इस विवरण में दो गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह  
घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एम० माटिन  
डैस्क अधिकारी

## आदेश

**विषय:-** तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में के, जी०-ओ० एस०-१०० / २ ब्लाक के ४५३० व० कि० मी० क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की मंजूरी ।

सं०: ओ-१२०१२/३२/१२-ओएन जी डी-४ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ के नियम ५ के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसके पश्चात आयोग कहा गया है) कृष्णा गोदावरी बेसिन में के जी०-ओ० एस०-१००/२ ब्लाक के ४५३० व० कि० मी० क्षेत्र में पेट्रोलियम भिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की ०१ अक्टूबर, १९९२ (०१-१०-१९९२) से ४ वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायलटी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैंड कन्डेन्सेट पर ४८१/- रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

स्वत्व शुल्क (रायलटी की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम ३० दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैंड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शनी बाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "क" "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा ।

(इ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ के नियम ११ की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग ५०,०००/- रुपये की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संरक्षण प्रत्येक वर्ष किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए   | 8-०० रुपये                                  |
| 2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए | ४०-०० रुपये                                 |
| 3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए   | २००-०० रुपये                                |
| 4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए  | ४००-०० रुपये                                |
| 5) लाइसेंस के नवीनीकरण के         | प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए ६००-०० रुपये । |

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ के नियम ११ के उपनियम (३) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से लगा तथा हर महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(अ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उप-करण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और / या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना की आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ब) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐस फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(इ) आयोग खुदाई / अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए वाथी-मीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(३) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं । यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा तिरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रति-नियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

अनुशुची—"क"

त्रुष्णा-नोदावरी बेसिन ब्लाक के जी-ओ एस-90/2 के लिए 4530 चर्ग किलो मीटर क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांक

पाईंट	अक्षांतर	देशांतर
-------	----------	---------

ब्लाक 1 बी

ए	16° 06" 52" एन	82° 47" 55" ई
---	----------------	---------------

बी	16° 06" 52" एन	82° 07" 00" ई
----	----------------	---------------

सी	15° 28" 17" एन	82° 07" 00" ई
----	----------------	---------------

डी	15° 28" 17" एन	82° 19" 10" ई
----	----------------	---------------

ई	15° 42" 49" एन	82° 48" 20" ई
---	----------------	---------------

अनुसूची—“ख”

अशोधित तेल, कॉर्सिंग कन्फेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण  
के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल	माह तथा वर्ष	(क) अशोधित तेल	कालम 2 और 3 को	टिप्पणी
कुल प्राप्त मी० टन की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	घटाकर प्राप्त मी०

1

2

3

4

5

## (ख) कॉर्सिंग हैड कन्फेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु- मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
--	--	--	---	---------

1

2

3

4

5

## (ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त धन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए धन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये धन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त धन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
------------------------------	--	--	--	---------

1

2

3

4

5

एतद्वारा मैं श्री..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ  
कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह  
घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर—

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एम० मार्टिन  
डैस्क अधिकारी

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1993

## संकल्प

सं. एस.सी.-1(5)/93-डी-3 (.)—भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के दिनांक 31-10-91 के संकल्प सं. एस.सी.-1(1)/91-डी-3 में अधिकार संशोधन करते हुए इस्पात उपभोक्ता परिषद में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाता है :—

1. लुधियाना इलैक्ट्रोलेटर्स एसोशिएशन  
लुधियाना-141003.
2. दुर्गपुर स्माल इन्डस्ट्रील एसोशिएशन  
दुर्गपुर-713216.
3. श्री पवन सच्चदेव  
इस्पात उद्योग  
खना (पंजाब)
2. अन्य सभी शते अपरिवर्तनीय रहेंगी।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों जिसमें प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी शामिल हैं, और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी दादस्यों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

संतोष नौटियाल,  
संयुक्त सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th April 1993

## CORRIGENDA

No. 68-Pres/93.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 54-Pres/90 dated the 26th January, 1990, published in Part-I, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday the 28th July 1990 relating to "Mention-in-Despatches" :—

*For*—S. No. 84 13613007 Lance Naik Jash Thakur Singh, 9 Para Commando

*Read*—S. No. 84 13613007 Lance Naik Jas Thaker Singh, 9 Para Commando

G. B. PRADHAN,  
Director

No. 69-Pres/93.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 55-Pres/91 dated the 26th January, 1991, published in Part-I, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday the 27th April 1991 relating to the award of "Vir Chakra" :—

*For*—S. No. 2 13613007 Havildar Jash Thakur, Parachute Regiment (Posthumous)

(Wherever it occurs)

*Read*—S. No. 2 13613007 Havildar Jas Thaker Singh, Parachute Regiment (Posthumous)

G. B. PRADHAN,  
Director

## खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1993

## संकल्प

सं. 12/1/91-खान-6 (.) :—इस मंत्रालय के दिनांक 19-2-1992 के समसंबद्धक संकल्प के क्रम में, भारत सरकार ने खनिज सलाहकार परिषद के गठन में प्रविष्टि सं. 2 और 3 में निम्नलिखित दो सांसदों को नामित करने का और निर्णय किया है :—

1. श्री भैरू लाल मीणा, सांसद, लोक सभा।
2. डा० एन० तुलसी रेडी, सांसद, राज्य सभा।

## आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, महानियंत्रक, भारतीय खान व्यूरो, महानियंत्रक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता, परमाणु ऊर्जा विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, महासागर विकास विभाग, खनिज और धातु व्यापार निगम को प्रेषित किया जाए।

दिवाकर देव,  
संयुक्त सचिव

No. 70-Pres/93.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 96-Pres/92 dated the 26th January, 1992, published in Part-I, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday the 4th July, 1992, relating to the award of "Vishisht Seva Medal" :—

*For*—S. No. 94 G/161718 Supdt. ER Gde II, Satish Chander

*Read*—S. No. 94 G/161718 Supdt. BR Gde II, Satish Chander

G. B. PRADHAN,  
Director

## (DEPARTMENT OF ELECTRONICS)

New Delhi-110 003, the 3rd March 1993

## RESOLUTION

No. RE/7.27/93.—In continuation to this Department's Resolution of even number dated 30th July, 1990, the President is pleased to reconstitute the Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA), also known as the Department of Electronics (DoE) Advisory Board, with immediate effect.

02. This Standing Committee is needed, as recently stressed by the Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG), in order to tap the creative energies and ideas of the people themselves, and for involving voluntary agencies and non-governmental organisations (VAs and NGOs) in all aspects of government, in light of the liberalised economic policies of the government. SCOVA is expected to explore all means for effective participation of the people along with self-managed institutions in ensuring

that the benefits of electronics reach the common man in every walk of life. SCOVA should continually identify VAs/NGOs which could get involved in those aspects of DoE's work which need greater interactions with the members of the public. Such aspects can be (i) identification of selected thrust areas for research and development; (ii) inter-se allocation of funds between various DoE programmes and missions; (iii) reviewing ultimate reach various councils and projects, etc.

3. SCOVA will function to achieve the following objectives :

3.1 Provide feedback to DoE on implementation of those programmes, especially R&D and technology-diffusion programmes, which affect the life of the common man.

3.2 Enable VAs/NGOs to serve as a sounding board for DoE policies and programmes, and even for judging the efficacy and desirability of policies and programmes under contemplation.

3.3 Continuously explore diverse mechanisms for effective participation of VAs/NGOs in the work of DoE.

4. The revised composition of the committee will be as under :

Chairman

1. Secretary, Deptt. of Electronics.

Members

2. Managing Trustee,  
Voluntary Organisation in Interest  
of Consumer Education (VOICE).

3. General Manager (Innovative RD),  
National Bank for Agriculture  
& Rural Development (NABARD).

4. Chairman, National Open-School.

5. President,  
Society for Electronics &  
Computer Technology (SECT), Bhopal.

6. Director,  
Centre for Applied Research  
in Electronics.  
Indian Institute of Technology, Delhi.

7. President,  
Institute for Research  
in Information Science.

8. Dr. Parmeshwar Rao,  
Secretary,  
Bhagavatula Charitable Trust, A. P.

9. Dr. Subrata Sinha,  
President,  
Peoples Science Network.

10. Director,  
Rural Devl. Training Centre,  
Ramakrishna Mission,  
Narendrapur, W. B.

11. Shri M. R. Chakravarty,  
Director,  
Centre for Electronics  
Design & Technology (CEDT), Imphal.

12. Shri Joe Madiath,  
Executive Director,  
Gram Vikas, Orissa.

13. Shri Prembhai,  
President  
Banawasi Sewa Ashram, U.P.

14. Shri Sanjay Ghosh,  
URMUL Trust, Rajasthan.

Member Secretary

15. Dr. Vinay Dharmadhikari,  
Director,  
Deptt. of Electronics.

5. The following will be standing invitees to SCOVA meetings :

1. Head of Standardisation, Testing & Quality Control (STQC) Directorate, DoE.

2. Head of Control & Instrumentation Division, DoE.

3. Head of Telecommunication Division, DoE.

4. Head of R&D Co-ordination Division, DoE.

6. Economic Adviser, DoE.

6. Representative of Office of Development Commissioner, Small Scale Industries (DC-SSI).

6. The Chairman may authorise the Member-Secretary to co-opt one or more eminent individuals whose participation in this forum may be found useful.

7. The term of office for non-official members will be for a period of two years from the date of issue of this notification.

8. TA/DA to non-official members for attending to the activities and meetings of this SCOVA will be provided as per provisions of normal department policies.

9. The expenses for the meetings will be authorised by the Member-Secretary under the budget Rural Electronics.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be indicated to all the State Governments, Union Territories, and that the resolution may be published in the Gazette of Government of India for general information.

Dr. PRONAB SEN,  
Jt. Secy. & Economic Adviser

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd April 1993

ORDER

Subject : —Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for KG-OS-90/1 Block area measuring 4367 sq. kms, in Krishna Godavari Basin.

No. O-12012/31/92-ONG.D.IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules, 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan,

Dehra Dun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 1st October, 1992 (01-10-1992) for KC-OS-90/1 Block area measuring 4367 sq. kms., in Krishna Godavari Basin, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the term and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :—

(i) Rs. 481/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

(i) Rs. 8/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas

and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

#### SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of KG-OS-90/1 Block area measuring 4367 sq. kms., in Krishna Godavari Basin.

Point	Latitude	Longitude
<b>Block-I 'A'</b>		
A	15° 21' 00" N	80° 40' 25" E
B	15° 21' 00" N	80° 34' 10" E
C	15° 50' 54" N	80° 31' 31" E
D	14° 58' 15" N	80° 03' 46" E
E	14° 58' 40" N	80° 40' 25" E

**SCHEDULE 'B'**

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

**A. Crude Oil**

Total No. of Metric tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

**B. Casing-head condensate**

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less Columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

**C. Natural Gas**

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri \_\_\_\_\_ do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

M. MARTIN,  
Desk Officer

## ORDER

Subject : —Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for KG-OS-90/2 Block area measuring 4530 sq. kms., in Krishna Godavari Basin.

No. O-12012/32/92-ONG.D.IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 01st October, 1992 (01-10-1992) for KG-OS-90/2 Block area measuring 4530 sq. kms., in Krishna Godavari Basin, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the term and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of petroleum.

(b) If any, minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 481/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'A' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

- (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
- (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
- (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
- (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
- (v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the

exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.
- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.
- (l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.
- (m) The Commission should ensure security of oceanographic data.
- (n) The entire data is processed in India.
- (o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.
- (p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

## SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of KG-OS-90/2 Block area measuring 4530 sq. kms., in Krishna Godavari Basin.

Points	Latitude	Longitude
<b>Block-I 'B'</b>		
A	16° 06' N	82° 47' 55"E
B	16° 06' N	82° 07' 00"E
C	15° 28' N	82° 07' 00"E
D	15° 28' N	82° 19' 10"E
E	15° 42' N	82° 48' 20"E

## SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for  
Area

Month and Year

A—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic Metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri \_\_\_\_\_ do hereby solemnly and sincerely declare, and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

M. MARTIN,  
Deputy Officer

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 25th May 1993

## RESOLUTION

No. SC-1(5)/93-D.III (.)—In partial modification of Government of India, Ministry of Steel, Resolution No. SC-1 (1)/91-D.III, dated 31st October, 1991, the following members are included in the Steel Consumers Council :

1. The Ludhiana Electroplaters Association, Ludhiana-141 003.
2. Durgapur Small Industries Association, Durgapur-713 216.
3. Shri Pawan Sachdeva,  
Ispat Udyog,  
Khanna (Punjab).
2. All other terms and conditions remain unchanged.

## ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries and Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller & Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer Council.

ORDERED also that it be published in the Gazette of India for general information.

S. NAUTIYAL,  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 7th January 1993

## RESOLUTION

No. 12(1)/91-MVI(.)—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 19-2-92, the Government of India have further decided to nominate the following two Members of Parliament against entry No. 2 and 3 in the composition of the Mineral Advisory Council :—

1. Shri Bheru Lal Meena, MP, Lok Sabha.
2. Dr. N. Thulasi Reddy, MP, Rajya Sabha.

## ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, Controller General, Indian Bureau of Mines, Director-General Geological Survey of India, Calcutta, Department of Atomic Energy, Ministry of Environment and Forest, Department of Ocean Development, Minerals and Metals Trading Corporation.

DIVAKAR DEV,  
Jt. Secy.

